

संपादकीय

इतिहास का अटल दौर

पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर एक पूरा कार्यकाल डूबे प्रधानमंत्री के रूप में यही इतिहास रहा अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन यह तो सिर्फ अवधि की बात हुई, उस अवधि में जो काम उन्होंने किया, उसके मूल्यांकन के लिए वक्त को फुर्सत से बैठना पड़ेगा। यह ऐसा काम नहीं है कि चलते-चलते लगे हाथों निपटाया जा सके। अगर राजनीतिक कद, बतौर प्रधानमंत्री लिए गए ऐतिहासिक फैसले और सर्वस्वीकार्यता डूबे तीन कसौटियों पर देखा जाए तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटलबिहारी वाजपेयी के बीच शायद ही कोई और प्रधानमंत्री आए। पंडित नेहरू ने अगर आधुनिक भारत की मजबूत नींव डाली तो वाजपेयी ने एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा दिलाकर उसे बुलदियों तक पहुंचाया। कश्मीर का मसला आजाद भारत की एक ऐसी समस्या रही है जिससे देश के सभी प्रधानमंत्री जुड़ते रहे, लेकिन वह वाजपेयी ही हुए जिन्होंने 'इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत' के रूप में उसे देखने का एक ऐसा व्यापक नजरिया दिया, जो इस मसले से जुड़े सभी पक्षों के लिए मिसाल बन गया है। आश्चर्य नहीं कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पहले 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में उसी नजरिए का हवाला देते हुए उसे अपनी नीतियों की भी प्रमुख कसौटी घोषित किया। यह तय माना जा सकता है कि जब भी कश्मीर समस्या के समाधान की कोई महत्वपूर्ण कोशिश होगी, तो उसे इसी कसौटी से होकर गुजरना होगा। मगर वाजपेयी के लंबे राजनीतिक जीवन का महज एक हिस्सा रहा है उनका प्रधानमंत्रित्व काल। एक सांसद के रूप में उनके भाषणों का असर इसी एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि लोकसभा सदस्य के उनके पहले कार्यकाल में ही उनका भाषण सुनकर पंडित नेहरू ने कह दिया था कि वह एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद संसद में प्रतिपक्ष के एक नेता के तौर पर सरकार की तारीफ का रेकॉर्ड भी लोकसभामें उन्होंने के नाम दर्ज है। आज भी याद किया जाता है कि बांग्लादेश युद्ध में जीत के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा था। नब्बे के दशक में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहराव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुआई की पेशकश की तो वे यह सोचकर हिचकें नहीं कि वहां मिली सफलता का श्रेय सरकार ले जाएगी जबकि विफलता का दोष उनके हिस्से आएगा।

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले ऋण को चीन की सहायता के रूप में देव रहे हैं। उनका मानना है की मुद्रा कोष द्वारा दिए गये डोनाल्ड ट्रंप मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले ऋण को चीन की सहायता के रूप में देव रहे हैं। उनका मानना है की मुद्रा कोष द्वारा दिए गये ऋण का उपयोग बेल्ट रोड बनाने में किया जायेगा, जिसका अंततः लाभ चीन को होगा जो कि अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। अतः पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका के बीच में कठिन रास्ता निकालना है। पूर्व के अनुभव को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान अपने इस मनसूबे को पूरा करने में सफल होगा और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बनाना जारी रहेगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन से यूरोप तथा अमेरिका तक माल ले जाने का भी एक सुगम मार्ग बनाया जायेगा। इससे चीन में बने माल को अफ्रीका तथा यूरोप पहुंचाने का खर्च कम पड़ेगा। अमेरिका की तुलना में चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ेगी। अमेरिका के माल को यूरोप में पहुंचाना पूर्ववत् समुद्री जहाजों से कठिन रहेगा जबकि चीन का माल बेल्ट रोड के माध्यम से अफ्रीका तथा यूरोप कम खर्च में पहुंच जायेगा। भारत के लिए यह प्रकरण कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। भारत ने बेल्ट रोड का विरोध इस बिंदु पर किया है कि उसका एक हिस्सा गिलगित के पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मध्य से गुजरता है। इसे भारत अपनी सम्प्रभुता पर आक्रमण मान रहा है जो कि सही है। भारत का विरोध राजनीतिक दृष्टि से उचित है। लेकिन बेल्ट रोड के बनने से चीन के माल का अफ्रीका और यूरोप को पहुंचाना आसान हो जायेगा परन्तु भारत के माल का उन्हीं देशों को पहुंचाना पूर्ववत् कठिन रह जायेगा। हम चीन से प्रतिस्पर्धा करने में उसी प्रकार पीछे हो जायेंगे, जिस प्रकार अमेरिका पीछे हो जायेगा। अतः हमें कोई युक्ति निकालकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा माल भी यूरोप तथा अफ्रीका उतनी ही आसानी से पहुंच सके, जितना कि चीन का माल पहुंच रहा है और हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति में कमी न आये। एक सम्भावना यह है कि भारत चीन पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के बीच से भारत को भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जोड़ने की सड़क उपलब्ध करायी जाए। यानी भारत का माल कश्मीर, फिर पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर, फिर अफगानिस्तान के रास्ते बेल्ट रोड के माध्यम से अफ्रीका तथा यूरोप पहुंच सके। ऐसा हो जाने से भारत की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ जाएगी और भारत को भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का लाभ मिलेगा। यहां बताते चलें कि भारत द्वारा लिखित अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर बेल्ट रोड का विरोध किया जा रहा है जो कि चीन के लिए एक समस्या है। विशेषकर ब्रिक्स देशों द्वारा बनाये गये न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की अच्छी पैठ है। इस बैंक द्वारा भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए ऋण दिया जा रहा है। भारत चीन पर दबाव डाल सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर वह बेल्ट रोड का विरोध करना बंद कर देगा, यदि चीन पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के मध्य से भारत को बेल्ट रोड से जुड़ने का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। चीन के साथ सम्बन्धों को हमें दो मायनों में देखना चाहिए। आज विश्व की 75 प्रतिशत जनता भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों में रहती है। जबकि इनके पास विश्व की केवल 25 प्रतिशत आय है। दूसरी तरफ यूरोप, जापान और अमेरिका में केवल 25 प्रतिशत जनता रहती है। जबकि इनके पास 75 प्रतिशत आय है। इसलिए बेल्ट रोड के माध्यम से चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों का उठना मूलतः वैश्विक असंतुलन को ठीक करने की तरफ एक सार्थक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चीन के साथ जो पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर का मसला है, वह हमें इस योजना से जुड़ने से रोक रहा है। अतः भारत का प्रयास होना चाहिए कि विकासशील देशों के बड़े हित को साधने के लिए जरूरत हो तो छोटे सामरिक हितों का रास्ता निकाल कर अपने आर्थिक हित को साधना चाहिए। बेल्ट रोड से अपने को अलग रखकर भारत अपने को यूरोप तथा अफ्रीका के बाजार से दूर कर लेगा जो कि अंततः भारत की मैनुफैक्चरिंग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत ही हानिप्रद सिद्ध होगा। भारत एक और कार्य कर सकता है। हमारी महारथ सेवा क्षेत्र में है जैसे कॉल सेंटर, लीगल रिसर्च, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि। इन सेवाओं का हमें वैश्विक पाठ्यवे बनाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार चीन उत्पादित माल का वैश्विक पाठ्यवे बेल्ट रोड के माध्यम से बना रहा है। उत्पादित माल को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसलिए बेल्ट रोड बनाना जरूरी था। लेकिन सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अतः भारत को चाहिए कि इंटरनेट का वैश्विक पाठ्यवे बनाने का प्रयास करे। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सुरक्षा आदि के विभिन्न पहलू हैं, जिनको हल करके भारत को एक ग्लोबल इंटरनेट पाठ्यवे बनाना चाहिए जो कि चीन के बेल्ट रोड के सामने हमारी सेवाओं की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करेगा।

भरत झुनझुनवाला

पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व में चीन द्वारा बढ़ाये गये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का विरोध किया था लेकिन अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने उसी बेल्ट रोड का समर्थन किया है। उनका पलटी मारना यह दिखाता है कि बेल्ट रोड पाकिस्तान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बेल्ट रोड योजना में चीन से हिन्द महासागर तक पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित क्षेत्र के मध्य से रेल तथा रोड लाइनों का नया नेटवर्क बनाया जायेगा, जिससे चीन का माल हिन्द महासागर आसानी से पहुंच सके। इस कार्य के लिये पाकिस्तान की सरकार भारी मात्रा में धन खर्च कर रही है। पाकिस्तान के राजस्व का बड़ा हिस्सा बेल्ट रोड में लगने के कारण शेष खर्चों को वहन करने के लिए पाकिस्तान के पास राजस्व नहीं है। इमरान खान ने संकेत दिए हैं कि वे धन की इस कमी की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी ऋण की मांग करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले ऋण को चीन की सहायता के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है की मुद्रा कोष द्वारा दिए गये ऋण का उपयोग बेल्ट रोड बनाने में किया जायेगा, जिसका अंततः लाभ चीन को होगा जो कि अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है। अतः पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका के बीच में कठिन रास्ता निकालना है। पूर्व के अनुभव को देखते हुए हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान अपने इस मनसूबे को पूरा करने में सफल होगा और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को बनाना जारी रहेगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन से यूरोप तथा अमेरिका तक माल ले जाने का भी एक सुगम मार्ग बनाया जायेगा। इससे चीन में बने माल को अफ्रीका तथा यूरोप पहुंचाने का खर्च कम पड़ेगा। अमेरिका की तुलना में चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ेगी। अमेरिका के माल को यूरोप में पहुंचाना पूर्ववत् समुद्री जहाजों से कठिन रहेगा जबकि चीन का माल बेल्ट रोड के माध्यम से अफ्रीका तथा यूरोप कम खर्च में पहुंच जायेगा। भारत के लिए यह प्रकरण कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। भारत ने बेल्ट रोड का विरोध इस बिंदु पर किया है कि उसका एक हिस्सा गिलगित के पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मध्य से गुजरता है। इसे भारत अपनी सम्प्रभुता पर आक्रमण मान रहा है जो कि सही है। भारत का विरोध राजनीतिक दृष्टि से उचित है। लेकिन बेल्ट रोड के बनने से चीन के माल का अफ्रीका और यूरोप को पहुंचाना आसान हो जायेगा परन्तु भारत के माल का उन्हीं देशों को पहुंचाना पूर्ववत् कठिन रह जायेगा। हम चीन से प्रतिस्पर्धा करने में उसी प्रकार पीछे हो जायेंगे, जिस प्रकार अमेरिका पीछे हो जायेगा। अतः हमें कोई युक्ति निकालकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा माल भी यूरोप तथा अफ्रीका उतनी ही आसानी से पहुंच सके, जितना कि चीन का माल पहुंच रहा है और हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति में कमी न आये। एक सम्भावना यह है कि भारत चीन पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के बीच से भारत को भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जोड़ने की सड़क उपलब्ध करायी जाए। यानी भारत का माल कश्मीर, फिर पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर, फिर अफगानिस्तान के रास्ते बेल्ट रोड के माध्यम से अफ्रीका तथा यूरोप पहुंच सके। ऐसा हो जाने से भारत की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ जाएगी और भारत को भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का लाभ मिलेगा। यहां बताते चलें कि भारत द्वारा लिखित अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर बेल्ट रोड का विरोध किया जा रहा है जो कि चीन के लिए एक समस्या है। विशेषकर ब्रिक्स देशों द्वारा बनाये गये न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की अच्छी पैठ है। इस बैंक द्वारा भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए ऋण दिया जा रहा है। भारत चीन पर दबाव डाल सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर वह बेल्ट रोड का विरोध करना बंद कर देगा, यदि चीन पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के मध्य से भारत को बेल्ट रोड से जुड़ने का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। चीन के साथ सम्बन्धों को हमें दो मायनों में देखना चाहिए। आज विश्व की 75 प्रतिशत जनता भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों में रहती है। जबकि इनके पास विश्व की केवल 25 प्रतिशत आय है। दूसरी तरफ यूरोप, जापान और अमेरिका में केवल 25 प्रतिशत जनता रहती है। जबकि इनके पास 75 प्रतिशत आय है। इसलिए बेल्ट रोड के माध्यम से चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों का उठना मूलतः वैश्विक असंतुलन को ठीक करने की तरफ एक सार्थक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चीन के साथ जो पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर का मसला है, वह हमें इस योजना से जुड़ने से रोक रहा है। अतः भारत का प्रयास होना चाहिए कि विकासशील देशों के बड़े हित को साधने के लिए जरूरत हो तो छोटे सामरिक हितों का रास्ता निकाल कर अपने आर्थिक हित को साधना चाहिए। बेल्ट रोड से अपने को अलग रखकर भारत अपने को यूरोप तथा अफ्रीका के बाजार से दूर कर लेगा जो कि अंततः भारत की मैनुफैक्चरिंग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत ही हानिप्रद सिद्ध होगा। भारत एक और कार्य कर सकता है। हमारी महारथ सेवा क्षेत्र में है जैसे कॉल सेंटर, लीगल रिसर्च, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि। इन सेवाओं का हमें वैश्विक पाठ्यवे बनाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार चीन उत्पादित माल का वैश्विक पाठ्यवे बेल्ट रोड के माध्यम से बना रहा है। उत्पादित माल को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसलिए बेल्ट रोड बनाना जरूरी था। लेकिन सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अतः भारत को चाहिए कि इंटरनेट का वैश्विक पाठ्यवे बनाने का प्रयास करे। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सुरक्षा आदि के विभिन्न पहलू हैं, जिनको हल करके भारत को एक ग्लोबल इंटरनेट पाठ्यवे बनाना चाहिए जो कि चीन के बेल्ट रोड के सामने हमारी सेवाओं की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करेगा।



का विरोध राजनीतिक दृष्टि से उचित है। लेकिन बेल्ट रोड के बनने से चीन के माल का अफ्रीका और यूरोप को पहुंचाना आसान हो जायेगा परन्तु भारत के माल का उन्हीं देशों को पहुंचाना पूर्ववत् कठिन रह जायेगा। हम चीन से प्रतिस्पर्धा करने में उसी प्रकार पीछे हो जायेंगे, जिस प्रकार अमेरिका पीछे हो जायेगा। अतः हमें कोई युक्ति निकालकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जुड़ना चाहिए, जिससे हमारा माल भी यूरोप तथा अफ्रीका उतनी ही आसानी से पहुंच सके, जितना कि चीन का माल पहुंच रहा है और हमारी प्रतिस्पर्धा शक्ति में कमी न आये। एक सम्भावना यह है कि भारत चीन पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के बीच से भारत को भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जोड़ने की सड़क उपलब्ध करायी जाए। यानी भारत का माल कश्मीर, फिर पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर, फिर अफगानिस्तान के रास्ते बेल्ट रोड के माध्यम से अफ्रीका तथा यूरोप पहुंच सके। ऐसा हो जाने से भारत की प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ जाएगी और भारत को भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का लाभ मिलेगा। यहां बताते चलें कि भारत द्वारा लिखित अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर बेल्ट रोड का विरोध किया जा रहा है जो कि चीन के लिए एक समस्या है। विशेषकर ब्रिक्स देशों द्वारा बनाये गये न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की अच्छी पैठ है। इस बैंक द्वारा भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए ऋण दिया जा रहा है। भारत चीन पर दबाव डाल सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर वह बेल्ट रोड का विरोध करना बंद कर देगा, यदि चीन पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के मध्य से भारत को बेल्ट रोड से जुड़ने का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। चीन के साथ सम्बन्धों को हमें दो मायनों में देखना चाहिए। आज विश्व की 75 प्रतिशत जनता भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों में रहती है। जबकि इनके पास विश्व की केवल 25 प्रतिशत आय है। दूसरी तरफ यूरोप, जापान और अमेरिका में केवल 25 प्रतिशत जनता रहती है। जबकि इनके पास 75 प्रतिशत आय है। इसलिए बेल्ट रोड के माध्यम से चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों का उठना मूलतः वैश्विक असंतुलन को ठीक करने की तरफ एक सार्थक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चीन के साथ जो पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर का मसला है, वह हमें इस योजना से जुड़ने से रोक रहा है। अतः भारत का प्रयास होना चाहिए कि विकासशील देशों के बड़े हित को साधने के लिए जरूरत हो तो छोटे सामरिक हितों का रास्ता निकाल कर अपने आर्थिक हित को साधना चाहिए। बेल्ट रोड से अपने को अलग रखकर भारत अपने को यूरोप तथा अफ्रीका के बाजार से दूर कर लेगा जो कि अंततः भारत की मैनुफैक्चरिंग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत ही हानिप्रद सिद्ध होगा। भारत एक और कार्य कर सकता है। हमारी महारथ सेवा क्षेत्र में है जैसे कॉल सेंटर, लीगल रिसर्च, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि। इन सेवाओं का हमें वैश्विक पाठ्यवे बनाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार चीन उत्पादित माल का वैश्विक पाठ्यवे बेल्ट रोड के माध्यम से बना रहा है। उत्पादित माल को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसलिए बेल्ट रोड बनाना जरूरी था। लेकिन सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अतः भारत को चाहिए कि इंटरनेट का वैश्विक पाठ्यवे बनाने का प्रयास करे। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सुरक्षा आदि के विभिन्न पहलू हैं, जिनको हल करके भारत को एक ग्लोबल इंटरनेट पाठ्यवे बनाना चाहिए जो कि चीन के बेल्ट रोड के सामने हमारी सेवाओं की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करेगा।

एक समस्या है। विशेषकर ब्रिक्स देशों द्वारा बनाये गये न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की अच्छी पैठ है। इस बैंक द्वारा भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए ऋण दिया जा रहा है। भारत चीन पर दबाव डाल सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर वह बेल्ट रोड का विरोध करना बंद कर देगा, यदि चीन पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के मध्य से भारत को बेल्ट रोड से जुड़ने का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। चीन के साथ सम्बन्धों को हमें दो मायनों में देखना चाहिए। आज विश्व की 75 प्रतिशत जनता भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों में रहती है। जबकि इनके पास विश्व की केवल 25 प्रतिशत आय है। दूसरी तरफ यूरोप, जापान और अमेरिका में केवल 25 प्रतिशत जनता रहती है। जबकि इनके पास 75 प्रतिशत आय है। इसलिए बेल्ट रोड के माध्यम से चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों का उठना मूलतः वैश्विक असंतुलन को ठीक करने की तरफ एक सार्थक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चीन के साथ जो पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर का मसला है, वह हमें इस योजना से जुड़ने से रोक रहा है। अतः भारत का प्रयास होना चाहिए कि विकासशील देशों के बड़े हित को साधने के लिए जरूरत हो तो छोटे सामरिक हितों का रास्ता निकाल कर अपने आर्थिक हित को साधना चाहिए। बेल्ट रोड से अपने को अलग रखकर भारत अपने को यूरोप तथा अफ्रीका के बाजार से दूर कर लेगा जो कि अंततः भारत की मैनुफैक्चरिंग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत ही हानिप्रद सिद्ध होगा। भारत एक और कार्य कर सकता है। हमारी महारथ सेवा क्षेत्र में है जैसे कॉल सेंटर, लीगल रिसर्च, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि। इन सेवाओं का हमें वैश्विक पाठ्यवे बनाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार चीन उत्पादित माल का वैश्विक पाठ्यवे बेल्ट रोड के माध्यम से बना रहा है। उत्पादित माल को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसलिए बेल्ट रोड बनाना जरूरी था। लेकिन सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अतः भारत को चाहिए कि इंटरनेट का वैश्विक पाठ्यवे बनाने का प्रयास करे। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सुरक्षा आदि के विभिन्न पहलू हैं, जिनको हल करके भारत को एक ग्लोबल इंटरनेट पाठ्यवे बनाना चाहिए जो कि चीन के बेल्ट रोड के सामने हमारी सेवाओं की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करेगा।

एक समस्या है। विशेषकर ब्रिक्स देशों द्वारा बनाये गये न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत की अच्छी पैठ है। इस बैंक द्वारा भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए ऋण दिया जा रहा है। भारत चीन पर दबाव डाल सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों पर वह बेल्ट रोड का विरोध करना बंद कर देगा, यदि चीन पाकिस्तान पर दबाव डाले कि पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर के मध्य से भारत को बेल्ट रोड से जुड़ने का रास्ता उपलब्ध कराया जाए। चीन के साथ सम्बन्धों को हमें दो मायनों में देखना चाहिए। आज विश्व की 75 प्रतिशत जनता भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों में रहती है। जबकि इनके पास विश्व की केवल 25 प्रतिशत आय है। दूसरी तरफ यूरोप, जापान और अमेरिका में केवल 25 प्रतिशत जनता रहती है। जबकि इनके पास 75 प्रतिशत आय है। इसलिए बेल्ट रोड के माध्यम से चीन और पूर्वी एशिया के अन्य देशों का उठना मूलतः वैश्विक असंतुलन को ठीक करने की तरफ एक सार्थक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा चीन के साथ जो पाकिस्तान ऑक्सुपाइड कश्मीर का मसला है, वह हमें इस योजना से जुड़ने से रोक रहा है। अतः भारत का प्रयास होना चाहिए कि विकासशील देशों के बड़े हित को साधने के लिए जरूरत हो तो छोटे सामरिक हितों का रास्ता निकाल कर अपने आर्थिक हित को साधना चाहिए। बेल्ट रोड से अपने को अलग रखकर भारत अपने को यूरोप तथा अफ्रीका के बाजार से दूर कर लेगा जो कि अंततः भारत की मैनुफैक्चरिंग एवं कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत ही हानिप्रद सिद्ध होगा। भारत एक और कार्य कर सकता है। हमारी महारथ सेवा क्षेत्र में है जैसे कॉल सेंटर, लीगल रिसर्च, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इत्यादि। इन सेवाओं का हमें वैश्विक पाठ्यवे बनाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार चीन उत्पादित माल का वैश्विक पाठ्यवे बेल्ट रोड के माध्यम से बना रहा है। उत्पादित माल को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसलिए बेल्ट रोड बनाना जरूरी था। लेकिन सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अतः भारत को चाहिए कि इंटरनेट का वैश्विक पाठ्यवे बनाने का प्रयास करे। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सुरक्षा आदि के विभिन्न पहलू हैं, जिनको हल करके भारत को एक ग्लोबल इंटरनेट पाठ्यवे बनाना चाहिए जो कि चीन के बेल्ट रोड के सामने हमारी सेवाओं की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार करेगा।

खेल

सिनसिनाटी : जोकोविच और सिलिच में होगी सेमीफाइनल भिड़ंत

सिनसिनाटी। पूर्व नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी मास्टर्स खिताब के और करीब पहुंच गए हैं और उन्होंने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के फाइनलिस्ट जोकोविच ने तीसरे राउंड में थिगोर दिमित्रोव को 2-6, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। इसके बाद उन्होंने दिन के अपने अगले मुकाबले में भी कमाल का प्रदर्शन किया और कनाडा के मिलोस राओनिक को 7-5, 4-6, 6-3 से मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। विंबलडन चैंपियन जोकोविच का एक दिन पहले बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा था। इसके बाद शनिवार को जोकोविच ने दो मैच खेले और दोनों में ही शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। जोकोविच की अब मारिन सिलिच से भिड़ंत होगी।



ने बारिश के कारण देर से हुए तीसरे दौर के मैच में हंगरी के मार्टन फुकोसोविच को 6-4 6-3 से मात दी। चौथे वरीय जुआन मार्टिन डेल पोत्रो ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को 7-6 6-7 6-2 से हराया जबकि सातवें वरीय मारिन सिलिच ने रूस के युवा कारेन खचानोव पर 7-6, 3-6, 6-4 से जीत दर्ज की। डेल पोत्रो का सामना अब बेल्जियम के 11वें वरीय डेविड गोफिन से होगा जिन्होंने विंबलडन के फाइनल में पहुंचे और छठे वरीय केविन एंडरसन को 6-2, 6-4 से पराजित किया।

हालेप और एलिना अंतिम-8 में

महिलाओं के वर्ग में सिमोना हालेप और एलिना स्वितोलिना ने अंतिम-8 में प्रवेश किया। शीर्ष वरीय हालेप ने वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की 16वीं वरीय एशले बार्टी को 7-5 6-4 से हराया और अब वह यूक्रेन की लेसिना सुरेंको के सामने होंगी। यूक्रेन की पांचवीं वरीय स्वितोलिना ने 16 वर्षीय अमेरिकी अमांडा एनिसिमोवा को 6-4 6-4 से मात दी। स्वितोलिना अब क्रॉटियर फाइनल में किकी बर्टंस से भिड़ेंगी जिन्होंने एनेट कोटावेट को 6-3, 2-6, 6-3 से पराजित किया।

बोल्ट पेशेवर फुटबॉलर बनने के सपने के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे

सिडनी। जमैका के महान धावक उसैन बोल्ट फुटबॉल में अपने करियर को लेकर गंभीर हैं और पेशेवर फुटबॉलर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वह वहां ए-लीग क्लब के साथ ट्रायल शुरू करेंगे। आठ बार के ओलिंपिक चैंपियन बोल्ट को ए-लीग की क्लब सेंट्रल कोस्ट मारिनर्स ने खुद को साबित करने का मौका दिया गया जिसके तहत वह टीम से अनिश्चितकाल के लिए जुड़े रहेंगे। बोल्ट इस क्लब से अनुबंध प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धरती के सबसे तेज धावक माने जाने वाले बोल्ट ने कहा है कि वह पेशेवर फुटबॉलर बनने को लेकर गंभीर हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। 31 बरस के बोल्ट ने कहा, 'मैं हमेशा फुटबॉल को लेकर गंभीर रहा हूँ और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि किस चीज का बना हूँ। यह हकीकत है। मैं अपने ट्रेक और फील्ड करियर के आखिरी दिनों से कह रहा हूँ कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ।'



क्रोएशिया के डेनियल सुबासिच ने फुटबॉल से संन्यास लिया

जाग्रेब। वर्ल्ड कप उपविजेता क्रोएशिया के गोलकीपर डेनियल सुबासिच ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रोएशिया फुटबॉल महासंघ (एचएनएस) की ओर से बुधवार को जारी बयान में सुबासिच ने कहा कि अब फुटबॉल को अलविदा कहने का समय आ गया है। 33 वर्षीय सुबासिच ने कहा कि 10 साल राष्ट्रीय टीम से जुड़े रहने के बाद अब अलविदा कहने का समय आ गया है। सुबासिच ने कहा, 'मैंने विश्व कप से काफी पहले यह फैसला कर लिया था। मेरा सपना वर्ल्ड कप में टीम का प्रतिनिधित्व कर संन्यास लेने का था। रूस का विश्व कप मेरे करियर का सबसे भावुक क्षण था। सही का शुक्रिया।' सुबासिच ने पिछले महीने टीम को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में



पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने डेनमार्क के खिलाफ अंतिम-16 मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में गोल का बचाव कर टीम की जीत सुनिश्चित की थी। क्रॉटियर फाइनल में रूस और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन लाजवाब था। उनसे पहले टीम के स्ट्राइकर मारियो मोंटजुकिच और डिफेंडर वेदान कोर्लुका ने भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है।

मोहम्मद शमी को राहत, पत्नी हसीन जहां को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता

नई दिल्ली। भारतीय पेशेवर मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर हजाने के केस में उन्हें पश्चिम बंगाल की स्थानीय कोर्ट ने राहत दी है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने उनपर हजाने का केस दायर किया था, जिसमें अलीपुर कोर्ट ने जहां का दावा खारिज कर दिया है। हसीन और शमी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीन जहां ने क्रिकेटर शमी से गुजारा भत्ता के तौर पर प्रतिमाह 10 लाख रुपये की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने शमी की लड़की के लिए हजाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। शमी से कहा गया है कि उन्हें अपनी लड़की को हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर 80 हजार रुपये देने होंगे। **पत्नी ने लगाए थे गंभीर आरोप :** 27 वर्षीय शमी पर उनकी पत्नी ने इससे पहले काफी गंभीर आरोप लगाए



थे। हसीन ने शमी पर चरेल्ड हिंसा, शादी के बाद अफेयर से लेकर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए थे। हसीन ने यह भी कहा था कि शमी के एक पाकिस्तानी लड़की से संबंध हैं जो उन्हें पैसे देती है। मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन मैच फिक्सिंग के आरोपों में बीसीसीआई ने शमी को बेगुनाह पाया। बेगुनाही साबित होने के बाद ही उन्हें भारतीय टीम का नया कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था। **इंग्लैंड दौर पर हैं शमी :** पेशेवर मोहम्मद शमी फिलहाल टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौर पर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच फिलहाल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसमें मेजबान टीम 2-0 से आगे है। शमी ने टेस्ट सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में अच्छे प्रदर्शन करते हुए अब तक कुल 6 विकेट झटके हैं। उनके नाम 32 टेस्ट मैचों में 116 विकेट दर्ज हैं।

मैं यहां कुछ साबित करने नहीं आया हूँ: सुशील

जकार्ता। अनुभवी पहलवान सुशील कुमार को एशियाई खेलों से पहले एक टूर्नामेंट में हार से सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फॉर्म को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन उन्होंने दमखम बाकी होने का दावा करते हुए कहा कि वह यहां कुछ साबित करने नहीं आए हैं। ओलिंपिक में भारत की ओर से एकल स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी सुशील पिछले महीने जॉर्जिया में हुए लिबलिंसि ग्रां. प्री. में हार गए थे। 4 साल में यह पहला मौका था जब सुशील पहले बाउट में ही हार कर बाहर हो गए। वह एशियाई खेलों की तैयारी के लिए जॉर्जिया गए थे। सुशील से जब हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेपरवाह होकर कहा,

तो क्या हुआ। खिलाड़ी कभी जीतता है, तो कभी हारता है। असली खिलाड़ी वही है, जो हारने के बाद कड़ी मेहनत करके वापसी करता है। **जकार्ता।** अनुभवी पहलवान सुशील कुमार को एशियाई खेलों से पहले एक टूर्नामेंट में हार से सामना करना पड़ा, जिससे उनकी फॉर्म को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन उन्होंने दमखम बाकी होने का दावा करते हुए कहा कि वह यहां कुछ साबित करने नहीं आए हैं। ओलिंपिक में भारत की ओर से एकल स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी सुशील पिछले महीने जॉर्जिया में हुए लिबलिंसि ग्रां. प्री. में हार गए थे। 4 साल में यह पहला मौका था जब सुशील पहले बाउट में ही हार कर बाहर हो गए। वह एशियाई खेलों की तैयारी के लिए जॉर्जिया गए थे। सुशील से जब हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेपरवाह होकर कहा,



एशियन गेम्स-2018 युवा निशानेबाजों को मिलेगी कड़ी चुनौती

पालेमबांग। भारत के युवा निशानेबाज अनीश भानवाला, मनु भाकर और इलावेनिल वालारिवान यहां होने वाले एशियाई खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में पदक हासिल करने का प्रयास करेंगे लेकिन उनके लिए चीन और साउथ कोरिया कड़ी चुनौती पेश करेंगे। अनीश और मनु की उम्र क्रमशः 15 और 16 साल है। अनीश और मनु, दोनों कॉमनवेल्थ गेम्स की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीतकर सुर्खियों में रहे थे लेकिन राष्ट्रमंडल में चुनौती एशियाई खेलों की तुलना में इतनी कड़ी नहीं थी और देखा होगा कि वे दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। भारत ने गोल्ड कोस्ट में 7 स्वर्ण पदक जीते थे और देखा कि वे दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में इतने ही स्वर्ण पदक हासिल किये हैं। केवल चार निशानेबाज जसपाल राणा, रंजन सोबी, रणधीर सिंह और जीतू राय ही यहां सोने का तमगा जीत सके हैं। जसपाल कोच के तौर पर यहां टीम के साथ हैं, वह पहले ही युवाओं पर दिए जा रहे गैरजरूरी

ध्यान के बारे में बात कर चुके हैं। हालांकि वह उनके पदक जीतने की संभावनाओं से इनकार नहीं करते। मनु शुरुआती दिन अभियंका वर्मा के साथ पिस्टल मिक्सड टीम स्पर्धा में उतरेंगे। वह पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता का स्वाद चख चुकी हैं, उन्होंने मार्च में गुआंजोलाजा विश्व कप में 2 गोल्ड जीते और इसके बाद वह गोल्ड कोस्ट में पोलिडियम पर रहें। **अनीश के लिए एशियाई परीक्षा :** अनीश ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए और उन्हें सीनियर स्तर पर अपनी कर्बिलियत साबित करनी है, जिससे एशियाई खेल उनके लिए बड़ी परीक्षा होंगी। वहीं 19 वर्षीय इलावेनिल भी शानदार निशानेबाज हैं जिन्होंने साल के शुरू में विश्व रेकॉर्ड के साथ सिडनी जूनियर विश्व कप की 10 मीटर राइफल स्पर्धा का गोल्ड जीतकर सुर्खियां बटोरी थी